



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 ज्येष्ठ, 1940 (श०)

संख्या- 551 राँची, मंगलवार

5 जून, 2018 (ई०)

## जल संसाधन विभाग ।

अधिसूचना

1 जून, 2018

संख्या-1/पी.एम.सी./विविध/798/2017 (खण्ड-II)-485--झारखण्ड, जल, गैस, ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अध्यादेश, 2018 (झारखण्ड अध्यादेश-04, 2018) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

### झारखण्ड भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) नियमावली, 2018

- संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ :- (1) झारखण्ड भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) नियमावली, 2018 है।  
(2) इनका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य पर होगा।

(3) यह नियमावली अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी।

**2. परिभाषाएं :-** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) “अध्यादेश” से अभिप्रेत है, झारखण्ड भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अध्यादेश, 2018।

(ख) “सक्षम प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, अध्यादेश की धारा 3 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत अधिकारी।

(ग) “प्रारूप” से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्रारूप।

(घ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इसमें प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अध्यादेश में उनके लिए दिए गए हैं।

**3. सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति -** अध्यादेश के अधीन भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन हेतु निजी भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करने हेतु विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए “झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” के अन्तर्गत घोषित सक्षम प्राधिकार जो उप समाहर्ता से अन्यून स्तर का अधिकारी हो, सक्षम प्राधिकारी होगा।

**4. आवेदन किया जाना -** यथास्थिति, राज्य सरकार या निगम द्वारा भूमिगत पाइप लाइन हेतु निजी भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जित करने के लिए आवेदन पत्र प्ररूप - “क” के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन पत्र में संबंधित ग्रामों के नाम, भूमि-स्वामी/अधिभोगी का नाम तथा पिता/पति का नाम, खसरा क्रमांक, भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जित करने हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल तथा अवधि जिसमें भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन का कार्य किया जाएगा, की जानकारी अंतर्विष्ट की जाएगी तथा नक्शा जिसमें क्षेत्र अंकित किए गए हों, भी संलग्न किए जाएंगे।

**5. अधिसूचना का प्रकाशन तथा स्वामी को सूचना -** (1) आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी, आवेदक से प्राथमिक रूप से अनुमानित प्रतिकर की अस्सी प्रतिशत राशि जमा करने की मांग करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन मांगी गई राशि जमा कर दिए जाने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी अपने इस आशय की घोषणा, राजपत्र में, प्ररूप-ख में, अधिसूचना द्वारा करेगा कि भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन के लिए जनहित में, भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित किया जाना आवश्यक है। यह अधिसूचना, राजपत्र में प्रकाशित करने के साथ-साथ निम्नांकित स्थानों पर भी चस्पा कराई जाएगी:-

(क) कलक्टर कार्यालय के सूचना पटल पर,

(ख) सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय के सूचना पटल पर,

(ग) उस क्षेत्र में परिचालित होने वाले दैनिक समाचार-पत्रों में, जिनमें से एक हिन्दी में होगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी, भूमिस्वामी/अधिभोगी को निजी भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करने के संबंध में सूचना देगा। “प्ररूप - ग” में दी जाने वाली सूचना :-

- (क) भूमिस्वामी/अधिभोगी को व्यक्तिगत रूप से, अथवा,
- (ख) भूमिस्वामी/अधिभोगी के परिवार के किसी वयस्क व्यक्ति को, अथवा
- (ग) भूमिस्वामी/अधिभोगी को रजिस्टर्ड डाक से, तथा
- (घ) भूमिस्वामी/अधिभोगी के निवास में अथवा उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर चिपका करके, दी जा सकेगी,

**6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषणा का प्रकाशन** - धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित घोषणा में विहित कालावधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों के निपटारे के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी, धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, घोषणा ‘प्ररूप-घ’ में प्रकाशित कराएगा। धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख से उसमें उल्लिखित भूमि के उपयोग के अधिकार समस्त विल्लंगमों से मुक्त राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे।

**7. प्रतिकर का निर्धारण** - (1) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा प्रकाशित होने के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन की अवधि के लिए उसमें उल्लिखित भूमि से होने वाली फसल से आय की क्षति, वृक्षों का प्रतिकर एवं अन्य हानि का विनिश्चित निम्नलिखित रीति में करेगा:-

(क) किसी असिंचित भूमि को एक फसली तथा सिंचित भूमि को दो फसली माना जाएगा, यदि भूमि में विगत भूमि तीन वर्षों में कोई फसल नहीं ली गई हो तो उस भूमि को “परती भूमि” माना जाएगा तथा ऐसी भूमि के लिए फसल से आय की क्षति की गणना नहीं की जाएगी। फसल से आय की क्षति की गणना निम्नानुसार की जाएगी:-

---


$$\text{फसल से आय की गणना} = \text{फसल की प्रमाणिक पैदावार} \times \text{फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य} \times 2$$


---

(ख) वृक्षों का प्रतिकर वन विभाग/उद्यानिकी विभाग के मत पर संगणित किया जाएगा, (2) उपनियम (1) के अधीन यथानिर्दिष्ट प्रतिकर के अतिरिक्त, यदि कोई हो, धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा के प्रकाशन के दिनांक को उस भूमि के बाजार मूल्य के दस प्रतिशत की दर से देय होगा। भूमि का बाजार मूल्य भू-अर्जन अधिनियम 2013, जिसका उल्लेख यहाँ नियम 3 में किया गया है, में वर्णित प्रक्रिया एवं निदेश का पालन करते हुए निर्धारित किया जायेगा।

8. **प्रतिकर की राशि की संगणना** - (1) राज्य सरकार या निगम, प्रतिकर की ऐसी राशि को मुजरा करने के पश्चात्, जो कि नियम 5 के उपनियम (1) के अनुसार पूर्व में ही जमा कर दी गई है, नियम 7 के अधीन निर्धारित प्रतिकर की राशि, सक्षम प्राधिकारी को धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर चेक द्वारा जमा करेंगे।
- (2) यदि प्रतिकर की राशि तीस दिन के भीतर जमा नहीं की जाती है तो यथास्थिति, राज्य सरकार या निगम उस पर, उस तारीख से, जिसको कि प्रतिकर जमा किया जाना था, उसे वास्तविक रूप से जमा करने की तारीख तक, नौ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज के भुगतान का दायी होगा तथा एक वर्ष बीत जाने पर 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देने के दायी होंगे।
9. **अधिकार के अर्जन पर कब्जा हटाना** - सक्षम प्राधिकारी, धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन भूमिस्वामी/अधिभोगी को प्रतिकर का भुगतान करते समय भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन हेतु विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार अर्जित करने के लिए 'प्ररूप-च' में भूमिस्वामी/अधिभोगी से प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।
10. **कब्जे का वापस दिलाया जाना** - यथास्थिति राज्य सरकार या निगम द्वारा भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन के कार्य समाप्ति पश्चात् भूमि समतल की जाएगी और अपने मूल रूप में लाई जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमिस्वामी/अधिभोगी को भूमि का कब्जा वापस दिया जाएगा। इस संबंध में, भूमिस्वामी/अधिभोगी से सक्षम प्राधिकारी द्वारा कब्जा वापसी प्रमाण-पत्र 'प्ररूप-छ' में लिया जाएगा।
11. **निरीक्षण आदि हेतु प्रवेश का अधिकार** - (1) भूमिस्वामी/अधिभोगी को भूमि का कब्जा वापस देने के पश्चात्, भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन निगम एवं निगम द्वारा अधिकृत व्यक्तियों का भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन के निरीक्षण, संधारण, सुधार उन्हें बदलने या हटाने के लिये जब आवश्यकता हो, भूमि में प्रवेश करने एवं कार्य करने की शक्ति होगी।
- (2) यदि भूमिस्वामी/अधिभोगी किसी प्रारूप, जिसमें उसके हस्ताक्षर की आवश्यकता है, में हस्ताक्षर करने से मना करता है, तो उस प्रारूप पर उसके स्थान पर सक्षम प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा बशर्ते कि संगत नियमों का पालन किया गया हो।
12. **अधियाचक द्वारा उपयोग के अधिकारों के अर्जन की लागत:-** (1) अधियाचक द्वारा अधिकारों के अर्जन में स्थापना व्यय एवं आकस्मिक व्यय नियम 7 में आकलित कुल मुआवजे का 5 प्रतिशत होगा।
- (2) नियम 12 (1) में आकलित स्थापना व्यय एवं आकस्मिक व्यय की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अधियाचक द्वारा समाहर्ता के पास जमा की जायेगी। समाहर्ता इस राशि को जिला कोषागार के डिपोजित खाता में अथवा किसी सरकारी बैंक खाता, जो इस हेतु सक्षम प्राधिकार एवं उपायुक्त द्वारा संयुक्त रूप से परिचालित हो, में जमा करेंगे।

**13. अनुदेश जारी किया जाना** - राज्य सरकार के समय-समय पर, बनाए गए अध्यादेश/अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के क्रियान्वयन के संबंध में किन्हीं कठिनाईयों के निराकरण के लिए अनुदेश जारी कर सकेगी।

**प्ररूप-क**  
**(नियम-4 देखिए)**

प्रति,

सक्षम प्राधिकारी

.....  
.....

**विषय:-** अध्यादेश के अधीन निजी भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन के लिए आवेदन पत्र।

..... परियोजना के लिए अंचल ..... जिला ..... से अंचल..... जिला ..... तक परिवहन हेतु भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन का प्रस्ताव है। उक्त परियोजना के लिए भूमि का विवरण तथा भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन के लिए प्रस्ताव भूमि अर्जित करने हेतु नक्सा इसके साथ संलग्न है।

अतएव अध्यादेश के अधीन निजी भूमि में उपयोक्ता के अधिकारों के अर्जन के लिए की जाने वाली कार्रवाई संलग्न ब्यौरों में वर्णित है -

संलग्न - ब्यौरे

आवेदन

**ब्यौरे**

अनु. क्रमांक	ग्राम का नाम/ हल्का क्रमांक	भूमिस्वामी / अधिभोगी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन के लिए उपयोक्ता के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6

**प्ररूप-ख**  
**(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)**

क्रमांक ....., अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ..... परिवहन हेतु ग्राम ..... अंचल ..... जिला से ..... अंचल ..... जिला तक झारखण्ड राज्य में मेसर्स ..... द्वारा भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन का

प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, झारखण्ड भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अध्यादेश, 2018 की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अध्यादेश की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे झारखण्ड भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन बिछाने जाने के संबंध में झारखण्ड सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### अनुसूची

जिला	अंचल	ग्राम/हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5

सक्षम प्राधिकारी,

### प्ररूप-ग

#### (नियम-5 का (3) देखिए)

झारखण्ड भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अध्यादेश, 2018 (झारखण्ड अध्यादेश सं.-04, 2018) की धारा 3 की धारा (1) के अन्तर्गत ..... परियोजना हेतु भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन के लिए आपके स्वामित्व/अधिभोगी की निम्नलिखित भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन करने संबंधी राज्य सरकार के आशय की घोषणा अधिसूचना ..... दिनांक ..... राजपत्र में प्रकाशित की गई है।

जिला	अंचल	ग्राम/हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5

अतएव अध्यादेश के अधीन बनाए गए नियम 5 (2) के अधीन एतद् द्वारा आपको सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार/निगम द्वारा आपके स्वामित्व/अधिभोग की भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

सक्षम प्राधिकारी,

दिनांक- .....

स्थान- .....

**प्ररूप-घ****(नियम-6 देखिए)**

झारखण्ड भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अध्यादेश, 2018 (झारखण्ड अध्यादेश सं.-04, 2018) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अध्यादेश के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए से ..... ग्राम ..... अंचल ..... जिला ..... से ग्राम ..... अंचल ..... जिला ..... के लिए परिवहन हेतु भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन के प्रायोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक ..... को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर/ सक्षम प्राधिकारी नोटिस बोर्ड पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अध्यादेश की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार/निगम में निहित होगा।

जिला	अंचल	ग्राम/हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5

सक्षम प्राधिकारी,

दिनांक-.....

स्थान-.....

**प्ररूप-च****(नियम-9 देखिए)****कब्जा प्रमाण पत्र**

झारखण्ड भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अध्यादेश, 2018 की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन जारी घोषणा दिनांक ..... के अनुसार ..... परियोजना हेतु भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन के लिए स्वामित्व/अधिभोग की निम्नलिखित भूमि ..... के द्वारा उपयोग में लाई जाएगी।

अनु. क्रमांक	ग्राम का नाम/ हल्का क्रमांक	भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम	खसरा क्रमांक	भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन के लिए उपयोक्ता के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5

2. अध्यादेश की धारा 9 के अधीन फसल आय की क्षति, पेड़ों एवं अन्य क्षति का मुआवजा अवधारित किया गया है।

मद	प्रतिकर का प्रकार					
अनु. क्रमांक	फसल आय की क्षति का प्रतिकर	पेड़ों का मुआवजा	अन्य आस्तियों की क्षति का प्रतिकर	भूमि का अतिरिक्त प्रतिकर	प्रतिकर की कुल देय राशि	प्रतिकर प्राप्ति का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7

3. भूमि में उपयोक्ता के अधिकार अर्जित किए जाने के संबंध में दिनांक ..... को प्रतिकर एवं अतिरिक्त प्रतिकर भुगतान किए जाने पर उपरोक्त उल्लिखित भूमि की उपयोगता के अधिकार आज दिनांक ..... से ..... तक उपयोग में जाएंगे। भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन का कार्य विनिर्दिष्ट अवधि में पूर्ण नहीं होने पर कार्य अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।

सक्षम प्राधिकारी,

भू-स्वामी/अधिभोगी के हस्ताक्षर

दो गवाहों के हस्ताक्षर

(1) ..... नाम एवं पता

(1) ..... नाम एवं पता

**प्ररूप-छ****(नियम- 10 देखिए)****कब्जा वापसी प्रमाण पत्र**

1. झारखण्ड भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अध्यादेश, 2018 (झारखण्ड अध्यादेश सं.-04, 2018) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन जारी घोषणा दिनांक ..... के अनुसार ..... परियोजना हेतु भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन के लिए आपके स्वामित्व/अधिभोग की निम्नलिखित भूमि दिनांक ..... से ..... तक अर्जित की गई है।

अनु क्रमांक	ग्राम का नाम/हल्का क्रमांक	भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम	खसरा क्रमांक	भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन के लिए उपयोक्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5

2. अध्यादेश की धारा 7 के अधीन उक्त भूमि में उपयोक्ता के अधिकार अर्जन हेतु सम्पूर्ण मुआवजा भुगतान कर दिया गया है। इस विषय में कोई भी देय राशि शेष नहीं है।
3. उक्त समतलीकृत भूमि का कब्जा आज दिनांक ..... को आपको हस्तांतरित किया गया है।

सक्षम प्राधिकारी

भू-स्वामी/अधिभोगी के हस्ताक्षर

दो गवाहों के हस्ताक्षर

(1) ..... नाम एवं पता

(2) ..... नाम एवं पता

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

**डी.के.तिवारी,**

सरकार के अपर मुख्य सचिव ।

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

**डी.के.तिवारी,**

सरकार के अपर मुख्य सचिव ।



**Water Resources Department**

-----

**Notification****1<sup>st</sup> June, 2018**

**No-1/PMC/Vividh/798 /2017 (Part-II)-485** --In exercise of power conferred by Sub Section (1) of Section-16 of Jharkhand Water, Gas and Drainage Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Ordinance '2018. (Jharkhand Ordinance No-4, 2018), the Government of Jharkhand hereby makes the following Rules :-

**Jharkhand Water, Gas and Drainage Pipelines (Acquisition of Right of User in Land)****Rules, 2018****1. Short title, extent and commencement.-**

- (1) These rules may be called the Jharkhand Water, Gas and Drainage Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 2018.
- (2) They extend to the whole of Jharkhand.
- (3) These rules come into force from the date of notification.

**2. Definitions.-** In these rules, unless the context other wise requires;

- (a) "Ordinance" means the Jharkhand Water, Gas and Drainage Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Ordinance, 2018 (Jharkhand Ordinance No.4, 2018)
- (b) "Competent Authority" means the officer authorized as Competent Authority under rule 3.
- (c) "Form" means form appended to these rules;
- (d) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning assigned to them in the Ordinance and the General Clauses Act.

**3. Competent authority under the Act :-** For the acquisition of right of user in private land to lay the Water, Gas or Drainage Pipelines under the Ordinance any officer, not below the rank of Deputy Collector, who has been notified as the competent authority for the specified area under "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013" by State Government, shall be the competent authority for this purpose.

**4. Filing of Application.-** The application for the acquisition of right of user to lay the Water, Gas or Drainage Pipelines in Form A shall be submitted to the competent authority by the State Government or the Corporation, as the case may be. The application shall contain the information of the names of concerned villages, land owner/ occupier of the land and name of father / husband, Khasra number and area proposed for acquisition of right of user and the period for the laying of Water, Gas or Drainage Pipelines and shall also contain the area marked on the map.

**5. Publication of notification and notice to the owner.-**

(1) After the receipt of application, the competent authority shall ask the applicant to deposit eighty percent amount of preliminary estimated compensation.

(2) After payment of such amount as demanded under sub-rule (1), the competent authority shall declare his intention by notification in the official gazette in Form B that in the public interest the acquisition of right of user is necessary to lay the Water, Gas or Drainage Pipelines. This notification shall be published and affixed in the following places as well as in the official Gazette:-

(a) on the notice board of the office of the Collector;

(b) on the notice board of the office of the Competent Authority;

(c) in the daily news papers circulated in that locality from which one shall be in Hindi.

(3) The Competent Authority shall serve the notice to the landowner / occupier regarding the acquisition of right of user in private land. The notice in Form-C may be served :-

(a) in person to the land owner/ occupier; or

(b) in person to any adult person of family of land owner/ occupier; or

(c) by registered post to land owner / occupier; and

(d) by pasting notice on the house or his last known residence of the land owner/ occupier.

**6. Publication of declaration by competent authority.-** After the disposal of objections received within the prescribed period of the publication under sub—section (1) of section 4, the Competent Authority shall publish the declaration in Form ‘D’ by notification in official Gazette under sub-section (1) of section 5. The right of user in the land mentioned therein shall be vested in the State

Government / Corporation free from all the encumbrances from the date of publication of the declaration under sub-section (1) of section 5.

**7. Assessment of Compensation.-** (1) After the publication of declaration under sub—section (1) of section 5, the competent authority shall decide the loss of crop income, compensation of trees and other losses from the land mentioned therein for the period of laying of Water, Gas or Drainage Pipelines in the following manner :-

(a) Any unirrigated land shall be considered as single cropped and irrigated land shall be considered as double cropped. If no crops are taken in last three years, the land shall be deemed as "fallow land" and the loss of crop income shall not be calculated for such land. In other cases, the loss of crop income shall be calculated as follows :-

Calculation of Crop Income	=	Standard Outcome of Crop	X	Minimum Support price of crop	X	2
----------------------------	---	--------------------------	---	-------------------------------	---	---

(b) The compensation of trees shall be calculated based on the opinion of Forest/Horticulture Department.

(2) In addition to the compensation as referred under rule (1), if any, the compensation shall be payable at the rate of Ten Percent of the value of that land on the date of publication of the declaration under sub-section (1) of section 5. The value of the land shall be determined following the same procedures and guidelines, as are followed while acquiring the land under the Act of 2013, mentioned in rule 3.

**8. Computation of compensation amount.** (1) The State Government or the Corporation shall, after setting off the amount which has been already deposited in accordance with sub-rule (1) of rule 5, deposit the compensation amount determined under Rule 7 to the Competent Authority by cheque within the period of thirty days from the date of declaration under sub-section (1) of section 5.

(2) If the amount of compensation is not deposited within thirty days, the State Government or the Corporation, as the case may be, shall be liable to pay interest thereon at the rate of nine percent per annum from the date on which the compensation had to be deposited till the date of the actual deposit: and at the rate of 15 percent per annum after lapse of one year.

**9. Taking of possession on acquisition of right.-** The Competent Authority shall obtain the possession certificate in Form 'E' for acquisition of right of user to lay Water, Gas or Drainage Pipeline for the specified period from the land owner/ occupier at the time of

payment of compensation to the land owner / occupier under sub-section (3) of section 10 of the ordinance.

**10. Restoration of possession.-** After laying the Water, Gas or Drainage Pipelines, the land shall be levelled and restored as good as before, by the State Government, or the Corporation, as the case may be, and the possession of land shall be handed over by the Competent Authority. In this regard, the Competent Authority shall restore the possession handing over certificate in Form 'F' to the landowner / occupier.

**11. Right of entering for inspection etc.-** (1) After handing over the possession of land to the land owner / occupier, the Corporation who laid the Water, Gas or Drainage Pipelines the persons authorized by the Corporation shall have the power to enter in the land and do the work as found necessary for inspection, maintenance, repair, replacement or removal of the Water, Gas or Drainage Pipelines.

(2) If the land owner or occupier refuses to sign any form, which he or she is required to sign under these rules, the same shall be signed by the Competent Authority, provided the procedure under these rules has been followed.

## **12. Cost of acquisition of right of user by requisitioning body**

(1) The establishment charge and contingency cost for the right of user by requisitioning body / corporation shall be 5 percent of the total value of compensation assessed under rule 7.

(2) The requisitioning body / corporation shall deposit the establishment charge and the contingency cost, as calculated under rule 12 (1) by way of bank draft to the Collector and the Collector shall deposit the cost of user land in the Deposit account in the district treasury or in a scheduled bank account maintained separately for this purpose to be jointly operated by Competent Authority and Deputy Commissioner.

**13. Issue of instructions.-** The State Government may issue instructions for removal of any difficulties regarding implementation of the provisions of the Act / Ordinance and the Rules framed thereunder from time to time.

**Form –A****(sec rule 4)**

To,

The Competent Authority,

.....

.....

Subject: Application for Acquisition of Right of User in Private land under Jharkhand Water, Gas and Drainage Pipelines Ordinance 2018.

There is proposal to lay Water, Gas or Drainage Pipelines from .....Anchal..... District to .....Anchal.....District for transportation of .....for .....Project. The land details and map of proposed land for acquisition to lay Water, Gas or Drainage Pipelines for the said project is enclosed herewith.

Therefore, an action to be taken for acquisition of right of user in private land described in the enclosed details.

Enclosure: - Details

-----  
Applicant**Details**

S.No	Name of Village / Circle No.	Name of Land owner / Occupier	Khasra No.	Total area (in hectare)	Land Required for Right of User for laying Water, Gas or Drainage Pipelines (in hectare)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

**Form-B****[See sub-rule (2) of rule 5]**

Whereas, it appears to the State government that it is necessary in the public interest that for the transportation of .....from village Anchal, .....District to ..... Anchal, .....District in Jharkhand State, Water, Gas or Drainage Pipelines should be laid by the M/s .....

And whereas, it appears to the State Government that for the purpose of laying the said Water, Gas or Drainage Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said Water, Gas or Drainage Pipelines is proposed to be laid which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub—section(1) of section 3 of the Jharkhand Water, Gas and Drainage Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Ordinance, 2018 (Jharkhand Ordinance No.04, 2018), the State Government, hereby, declare its intention to acquire the right of user therein.

Any person interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date of the publication of notification in the official Gazette under sub-section (1) of section 3 of the Ordinance, object in writing to the laying of Water, Gas or Drainage Pipelines to the Competent Authority appointed by Government of Jharkhand

**SCHEDULE**

<b>District</b>	<b>Anchal</b>	<b>Village/ Circle No.</b>	<b>Khasra No.</b>	<b>Land to be acquitted for Right of User (in hectare)</b>

**Competent Authority**

**Form—C****[ see rule 5 (3) ]**

A Notification No ..... dated .....has been published in the Gazette regarding declaration of the intention of the State Government to acquire the right of user in the following land of your ownership / occupancy to lay Water, Gas or Drainage Pipelines for the.....project under sub—section (1) of section 3 of the Jharkhand Water, Gas and Drainage Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Ordinance, 2018 (Jharkhand Ordinance No-04, 2018).

District	Anchal	Village / Circle No.	Khasra No.	Land to be acquitted for Right of User (in hectare)

Therefore, you are hereby informed under rule 5(2) framed under the Ordinance, that it is proposed to acquire the right of user in the land of your ownership / occupancy, by the State Government / Corporation.

Date .....

Competent Authority

Place .....

**Form—D****(see rule 6)**

Whereas by notification of the Competent Authority No ..... Date ..... issued under sub—  
 section (1) of section 3 of the Jharkhand Water, Gas and Drainage Pipelines (Acquisition of Right of  
 User in Land) Ordinance, 2018 (Jharkhand Ordinance No-04, 2018) (hereinafter referred to as the  
 said Act) the State Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified  
 in the Schedule appended to the notification for the purpose of laying the Water, Gas or Drainage  
 Pipelines for transportation of ..... from village ..... Anchal ..... District to .....  
 ..... village ..... Anchal, ..... District for ..... Project by .....

And that notification published in the official Gazette on ..... and pasted on the notice  
 board of the office of the Collector / Competent Authority, and the same has also been served to the  
 land owner/ occupier.

And whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said  
 Ordinance, the right of user in the land for laying the pipeline shall vest in the State Government /  
 Corporation free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

District	Anchal	Village / Circle No.	Khasra No.	Land to be acquitted for Right of User (in hectare)

Competent Authority



**Form - E**

(see rule 9)

**Possession Certificate**

1. As per declaration dated ..... issued under sub-section (1) of section 5 of the Jharkhand Water, Gas and Drainage Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Ordinance, 2018 (Jharkhand Ordinance No-04, 2018) the following land of your ownership / occupancy shall be used by .....for the laying of Water, Gas or Drainage Pipelines for .....project.

S.No	Village/ Circle No.	Name of Land owner/occupier	Khasra No.	Land to be acquitted for Right of User (in hectare)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

2. The compensation determined for the loss of income of crops, trees and other losses under section 9 of the Ordinance are as below :-

S.No.	Type of compensation				Total Payable amount of compensation	Date of Receipt of compensation.
	Compensation of Loss income of crops	Compensation of Trees	Compensation of loss of other assets if any	Additional Compensation of land		

3. The Right of User in land shall be utilized from today dated ..... upto .....for which the payment of compensation and additional compensation has been paid to you on dated .....for acquisition of right of user in above mentioned land. If the work of laying Water, Gas or Drainage Pipelines is not be completed in the specified period, the working period can be extended.

Signature of land owner / occupier

Competent Authority

Signatures of two witnesses.

1 .....Name &amp; address

2 .....Name &amp; address

**Form-F**

(see rule 10)

**Possession Return Certificate.**

1. As per declaration dated ..... issued under sub—section (1) of section 5 of the Jharkhand Water, Gas and Drainage Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Ordinance, 2018 (Jharkhand Ordinance No-04, 2018), the following land of your ownership/ occupancy has been acquired from the date.....to dated.....for the laying of Jharkhand Water, Gas or Drainage Pipelines for ..... project.

S.No	Name of Village / Anchal	Name of Land owner/occupier	Khasra No.	Land to be acquitted for Right of User (in hectare)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

2. Under section 7 of the Ordinance, the total compensation payment has been paid for acquisition of right of User in the above land. There is not any balance of payable amount in this regard.

3. The possession of above levelled land is handed over to you today dated .....

Signature of land owner / occupier

Competent Authority

Signatures of two witnesses.

1 ..... Name&amp; Address

2 ..... Name&amp; Address

By order of the Governor of Jharkhand,

**D.K. Tiwari,**  
Additional Chief Secretary to Government.

-----